

मौसम

अधिकतम तापमान 39.८

न्यूनतम तापमान 30.८

बाजार

सोना 101.700g

चांदी 106.000 kg

सत्य का स्वर

भारत संवाद

प्रयागराज, लखनऊ तथा मुम्बई से एक साथ प्रकाशित

संक्षिप्त समाचार
छात्र के आत्मदाह के विरोध में विपक्ष एकजुट, ओडिशा बंद का किया आह्वान

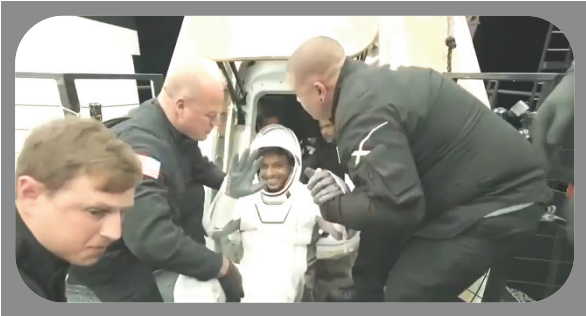
कांग्रेस सहित कम से कम आठ राजनीतिक दलों ने ओडिशा के एक छात्र की आत्मदाह के कारण हुई मौत पर ओडिशा बंद का आह्वान किया है। यह घटनाक्रम कांग्रेस और बीजू जनता दल (बीजद) कार्यकर्ताओं द्वारा भुवनेश्वर में एम्स के बाहर विरोध प्रदर्शन के कुछ घंटों बाद हुआ, जहां छात्रा का शनिवार, 12 जुलाई से इलाज चल रहा था।बालासोर के फकीर मोहन स्वायत्त महाविद्यालय की 20 वर्षीय छात्रा ने पिछले हफ़्ते खुद को आग लगा ली थी। छात्रा का आरोप था कि उसके कॉलेज के एक प्रोफेसर द्वारा कथित यौन उत्पीड़न के मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई।195 प्रतिशत तक जलने के कुछ दिनों बाद, सोमवार देर रात छात्रा को मृत घोषित कर दिया गया।भुवनेश्वर स्थित एम्स के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए, पार्टियों ने राज्य सरकार पर मामले को छुपाने का आरोप लगाया और उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज को बर्खास्त करने की मांग की।बीजद नेता सुलता देव ने कहा, पोस्टमॉर्टम रात में क्यों किया गया? शव रात में इसलिए लाया गया ताकि किसी को पता न चले। उन्होंने यह भी बताया कि बीजद नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की।

मणिपुर में भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद जब्त, दंगा-रोधी बंदूकें और आईईडी भी बरामद

मणिपुर पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) ने मंगलवार को पहाड़ी राज्य में 86 हथियार और 974 गोला-बारूद बरामद किए, जो पिछले कुछ वर्षों में घातक जातीय संघर्ष का गवाह रहा है। समाचार एजेंसी एएनआई ने मणिपुर डीजीपी कार्यालय के हवाले से बताया कि संयुक्त अभियान में, बलों ने इम्फाल पूर्व, इम्फाल पश्चिम, थैबल, काकचिंग और बिष्णुपुर जिले के इलाकों में ग्रेनेड, आईईडी, एके सीरीज और ईसास राइफलें, पिस्तौल, दंगा-रोधी बंदूकें और एसबीबीएल जल्ब किए। 13 जुलाई की रात और 4 जुलाई की सुबह, इसी तरह के एक अभियान में, मणिपुर पुलिस ने राज्य के पहाड़ी जिलों में व्यापक तलाशी अभियान के दौरान 200 से ज्यादा हथियार बरामद किए। ये छोपे अवैध हथियारों पर अंकुश लगाने और क्षेत्र में शांति बहाल करने के चल रहे प्रयासों का हिस्सा हैं। राज्य में कानून-व्यवस्था स्थिर रहने के बीच, पुलिस ने तलाशी अभियानों में हथियारों और गोला-बारूद का एक बड़ा जखीरा बरामद किया। ये अभियान मणिपुर पुलिस, असम वाइफल्स, सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा शुरू की गई व्यापक कार्रवाई का हिस्सा हैं। पिछले हफ़्ते, मणिपुर पुलिस ने नौ लोगों को गिरफ़्तार किया।

शुभआगमन
►►मिशन 14 दिन का था, पर 18 दिन चला। वहां 60 प्रयोग किए गए। इनमें 7 इसरो के थे। शुभांशु 263 किलो वैज्ञानिक सामान और डेटा ला रहे हैं। यह मिशन इसरो के लिए अहम है, क्योंकि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान 2027 में लॉन्च होना है। शुभांशु के मिशन पर 550 करोड़ खर्च हुए।

नयी दिल्ली। 15 जुलाई 2025 भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की 18 दिन की अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) यात्रा का समापन कर धरती पर लौट गए। सभी अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर आ रहा ड्रैगन यान कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में उतरा। उनके ड्रैगन कैप्सूल ने सोमवार शाम 4:45 बजे आईएसएस से अनडॉकिंग के बाद धरती की यात्रा शुरू की। शुभांशु एगिज ओम-4 मिशन के तहत 25 जून को दोपहर 12 बजे तीन अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ आईएसएस गए थे। तब पहुंचने में 28



शुभांशु शुक्ला के पिता से राजनाथ ने की बात, योगी बोले- भारत आपके स्वागत को उत्सुक

15 जुलाई 2025 भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की 18 दिन की अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) यात्रा का समापन कर धरती पर लौट गए। सभी अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर आ रहा ड्रैगन यान कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में उतरा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के पिता शंभू दयाल शुक्ला से बात की। शुभांशु 18 दिन बाद अंतराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर लौटे।

घंटे लगे थे, लेकिन वापसी 23 घंटे में पूरी होगी। शुभांशु आईएसएस पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं।

पिथौरागढ़ में बड़ा सड़क हादसा, सवारियों से भरा वाहन नदी में गिरा, 8 की मौत

सीएम धामी ने जताया दुख
मिली जानकारी के अनुसार, घटना मंगलवार शाम करीब 4 बजे की है. थल-पिथौरागढ़ मोटर मार्ग में मुवानी के पास सूनी पुल से एक वाहन (मैक्स जीप) अनियंत्रित होकर 100 फीट नीचे नदी में जा गिरा.



में वाहन के परखच्चे उड़ गए, हादसे में 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. मृतकों में दो सगे बहने हैं. सभी मृतक बोकटा क्षेत्र के निवासी हैं. मृतकों में तनुजा और विनीता आपस में सगी बहनें हैं, जो जो आईसी मुवानी में कक्षा 9वीं के छात्रा हैं. घायलों को 108 के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुवानी भेजा गया. जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर भेज दिया गया है. घटना की जानकारी मिलते ही बेरीनाग एसडीएम आशीष जोशी और तहसीलदार देवलथल और थानाध्यक्ष थल शंकर सिंह रावत के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची.

मैक्स हादसे में मृतकों का विवरण	पिथौरागढ़
सिमरन पुत्री कुंदन सिंह (उम्र 8 वर्ष), निवासी- बोकटा, पिथौरागढ़	राजेंद्र सिंह पुत्र किशन सिंह (उम्र 60 वर्ष), निवासी- बोकटा, पिथौरागढ़
तनुजा पुत्री चंद्र सिंह (उम्र 15 वर्ष), निवासी- बोकटा, पिथौरागढ़	होशियार सिंह पुत्र भीम सिंह (उम्र 65 वर्ष), निवासी- बोकटा, पिथौरागढ़
विनीता पुत्री चंद्र सिंह (उम्र 14 वर्ष), निवासी- बोकटा, पिथौरागढ़	शांति देवी पुत्री केशर राम (उम्र 50 वर्ष), निवासी- बोकटा, पिथौरागढ़
नरेंद्र सिंह पुत्र चंद्र सिंह (उम्र 40 वर्ष) वाहन चालक, निवासी- बोकटा,	दिकषा पत्नी पंकज सिंह (उम्र 28 वर्ष), निवासी- बोकटा, पिथौरागढ़

जिहाद असम में जनसांख्यिकीय बदलाव पर बोले हिमंत बिस्वा सरमा

असमिया लोगों को खत्म करने का जिहाद...

एजेंसी

नयी दिल्ली। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को राज्य में जनसांख्यिकीय बदलाव के अपने दावों को और पुष्टा करते हुए कहा कि स्थानीय समुदाय दबाव में हैं। उन्होंने इसे एक धर्म के लोगों द्वारा रणनीतिक अतिक्रमण बताया। गुवाहाटी में मीडिया को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि ये प्रवासी राजनीतिक प्रभाव हासिल करने के इरादे से विभिन्न क्षेत्रों की जनसांख्यिकीय रूपरेखा को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। हिमंत के अनुसार, राज्य सरकार ने मई 2021 से अब तक कई बेखुली अभियानों के जरिए 1.19 लाख बीघा से ज्यादा अतिक्रमित जमीन को खाली कराया



है। हालाँकि उन्होंने सीधे तौर पर उस समुदाय का नाम नहीं बताया जिसकी ओर वे इशारा कर रहे थे, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि बेदखल किए गए लोगों में से कई बंगाली भाषी मुसलमान हैं। एक प्रेस वार्ता में बोलते हुए, मुख्यमंत्री ने दावा किया कि वन

और सरकारी जमीन से बेदखल किए गए ज्यादातर लोगों के पास पहले से ही अपने मूल जिलों में जमीन है, लेकिन वे किसी कथित मकसद से असम के दूर-दराज के इलाकों में जा बसते हैं। उन्होंने कहा कि वन विनाश इन मुद्दों में से एक है। ये लोग उस जगह

66 गुवाहाटी में मीडिया को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि ये प्रवासी राजनीतिक प्रभाव हासिल करने के इरादे से विभिन्न क्षेत्रों की जनसांख्यिकीय रूपरेखा को बदलने का प्रयास कर रहे हैं।

की जनसांख्यिकी बदलने के लिए पलायन करते हैं। उन्होंने आगे बताया कि प्रवासी बाद में अपने नए ठिकानों पर मतदाता के रूप में अपना नाम दर्ज कराते हैं। उन्होंने दावा किया, और जब उनकी संख्या हजारों में हो जाती है, तो वे एक बड़ा वोट बैंक बन जाते हैं, और राजनीतिक नेता जंगल या सरकारी जमीन पर उनके शुरूआती अतिक्रमण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। उन्होंने समुदाय का नाम लिए बिना कहा, ये सभी लोग एक ही धर्म के हैं। असम के मुख्यमंत्री ने तीखी टिप्पणी



एजेंसी

नयी दिल्ली। एक नए राजनीतिक भूचाल में, महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी को कथित तौर पर अपनी पदयात्रा के दौरान पूर्वी चंपारण के तुरकौलिया में एक कार्यक्रम से बाहर जाने को कहा गया। यह घटना

○ स्थानीय मुखिया विनय कुमार साह ने उन्हें उस स्थल पर आने और पंचायत भवन में एक संगोष्ठी में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। हालाँकि, कार्यक्रम के दौरान उस समय तनाव बढ़ गया जब गांधी के एक सहयोगी ने कथित तौर पर महागठबंधन के समर्थन में राजनीतिक टिप्पणी की, जिससे मुखिया नाराज हो गए।

स्थल पर आने और पंचायत भवन में एक संगोष्ठी में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। हालाँकि, कार्यक्रम के दौरान उस समय तनाव बढ़ गया जब गांधी के एक सहयोगी ने कथित तौर पर महागठबंधन के समर्थन में राजनीतिक टिप्पणी की, जिससे मुखिया नाराज हो गए। जवाब में, विनय साह ने कथित तौर पर तुषार गांधी पर मंच का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया और महात्मा गांधी से अपने संबंध से इनकार करते हुए अंततः उन्हें कार्यक्रम स्थल से चले जाने को कहा।

कांवड़ यात्रा पथ पर ढाबों पर फिलहाल लगाना ही होगा वयूआर कोड: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी-उत्तराखंड सरकार से जवाब तो मांगा, लेकिन रोक नहीं लगाई

66 यूपी सरकार के वकील जितेंद्र कुमार सेठी ने कहा कि मामला संगीन है और हमें दो हफ्ते का वक्त चाहिए। जिसके बाद इ र।

एजेंसी

सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार की बड़ी जीत हुई है। वयूआर कोड मामले को लेकर याचिकाकर्ता ने याचिका दाखिल की थी, उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में 2

7 इसरो के थे। शुभांशु 263 किलो वैज्ञानिक सामान और डेटा ला रहे हैं। यह मिशन इसरो के लिए अहम है, क्योंकि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान 2027 में लॉन्च होना है। शुभांशु के मिशन पर 550 करोड़ खर्च हुए।

भारतीय सेना मानहानि मामले में राहुल गांधी का लखनऊ कोर्ट में सरेंडर

5 मिनट बाद मिली जमानत
यह मानहानि का मामला गांधी द्वारा अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सैनिकों के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणियों से जुड़ा है। अदालत के समन का पालन करते हुए, गांधी लखनऊ में सांसदों और विधायकों के लिए विशेष मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश हुए।



लखनऊ की एक अदालत ने जमानत दे दी है। जानकारी के अनुसार, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा की अध्यक्षता वाली एम्पी-एमएलए

राहुल गांधी ने क्या कहा?
यह विवाद 16 दिसंबर, 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान शुरू हुआ था। लखनऊ घाटी में हुई झड़पों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि बीजेपी सैनिक हमारे सैनिकों को पीट रहे हैं और कोई इत्र बारी में बवाल तक नहीं छुड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा था कि बीजेपी सैनिक हमारे सैनिकों को पीट रहे हैं। हालाँकि, भारतीय सेना ने कुछ दिन पहले ही 12 दिसंबर को एक आधिकारिक बयान जारी कर स्पष्ट किया था कि बीजेपी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें कड़ा और मार्कुल जवाब दिया गया। (बयान के अनुसार, बीजेपी सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा और दोनों पक्षों को केवल मामूली घोटें आईं।)

कथित अपमानजनक टिप्पणियों से जुड़ा है। अदालत के समन का पालन करते हुए, गांधी लखनऊ में सांसदों और विधायकों के लिए विशेष मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश हुए।

गोल्डन टेंपल को बम से उड़ाने की धमकी, लगातार दूसरे दिन आया धमकी भरा ईमेल

66 मंदिर परिसर में विस्फोटक रखे होने की चेतावनी वाले इस ईमेल के बाद एसजीपीसी अधिकारियों और पंजाब पुलिस दोनों ने तुरंत और समन्वित कार्रवाई शुरू कर दी है।



एजेंसी

अमृतसर के गोल्डन टेंपल को बम से उड़ाने की धमकी फिर से मिली है। धमकी भरा ईमेल लगातार दूसरे भी आया है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) को ईमेल के जरिए मिली बम की धमकी के बाद स्वर्ण मंदिर परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मंदिर परिसर में विस्फोटक रखे होने की चेतावनी वाले इस ईमेल के बाद एसजीपीसी अधिकारियों और

पंजाब पुलिस दोनों ने तुरंत और समन्वित कार्रवाई शुरू कर दी है। एसजीपीसी के मुख्य सचिव कुलवंत सिंह मन्नान ने पुष्टि की कि धमकी भरे ईमेल में आरडीएक्स की मौजूदगी और पवित्र स्थल को संभावित नुकसान का जिक्र था। हालाँकि ईमेल में समय का स्पष्ट विवरण नहीं था, फिर भी हमले की संभावित तारीख के रूप में सोमवार का अस्पष्ट उल्लेख था।

सम्पादकीय

आयकर विभाग की छापेमारी, राजनीतिक चंदे के फर्जी बिल

इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि भ्रष्ट नेताओं नौकरशाहों के पास से करोड़ों-अरबों रुपये की नकदी मिलती ही रहती है। यदि नेताओं नौकरशाहों की रिश्तखोरी पर सचमुच लगाम लगानी है तो नकदी के चलन को कम करना होगा और मनी ट्रेल का पता लगाने की कोई ठोस व्यवस्था भी करनी होगी।आयकर विभाग को राजनीतिक चंदे के फर्जी बिल लगाने वालों के खिलाफ देश भर में बड़े पैमाने पर छापेमारी करनी पड़ी। राजनीतिक चंदे के फर्जी बिल लगाकर आयकर से बचने का काम पहले भी होता रहा है।माना जाता था कि इसमें कुछ कमी आई होगी, लेकिन लगता है कि स्थिति जस की तस है। यदि वास्तव में ऐसा है तो इसका मतलब है कि राजनीतिक चंदे और आयकर संबंधी कानून ऐसे हैं कि लोग उनका दुरुपयोग आसानी से कर लेते हैं।यदि नियम-कानून कमजोर होंगे तो लोग उन्हें तोड़ने का काम करेंगे ही।यह ठीक है कि लोगों को जिम्मेदार होना चाहिए, लेकिन आखिर सरकार की भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है।समझना कठिन है कि वह राजनीतिक चंदे और आयकर से जुड़े कानून इस तरह के क्यों नहीं बना पा रही है कि उनका न्यूनतम दुरुपयोग हो सके और यदि लोग दुरुपयोग करें तो आसानी से पकड़ में आ जाए।बात केवल आयकर कानूनों की विसंगतियों की ही नहीं है।टैक्स संबंधी अन्य कानून भी खामियों से पूरी तौर पर मुक्त नहीं किए जा सके हैं।आयकर की तरह जीएसटी की भी चोरी होती है।लोग टैक्स बचाने के उपाय करें,यह तो समझ आता है, लेकिन अपने देश में इसके नाम पर कर चोरी खूब होती है।यह ठीक है कि कर संग्रह बढ़ रहा है, लेकिन उतना नहीं, जितना बढ़ना चाहिए।वैसे तो टैक्स चोरी दुनिया भर में होती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि भारत में भी वह होती रहे और उस पर कोई प्रभावी लगाम न लग पाए।टैक्स चोरी अमीर तबका भी करता है और उसकी देखादेखी मध्यमवर्ग भी।टैक्स चोरी पर शायद पूरी तौर पर तो रोक नहीं लगाई जा सकती, लेकिन टैक्स चुपाने वाले लोगों के मन में कानून का थोड़ा भय भी होना चाहिए।यह शुभ संकेत नहीं कि अपने देश में तमाम दावों के बाद भी टैक्स ढांचे में पर्याप्त सुधार नहीं किया जा सका है।पता नहीं टैक्स ढांचे में जरूरी सुधार करने में देरी क्यों हो रही है? जो भी हो इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि नोटबंदी के बाद यह जो दावा किया गया था कि नकदी का चलन कम हो जाएगा, वह थोथा ही साबित हुआ।किसी को इस पर विचार करना चाहिए कि नकदी का इतना अधिक चलन क्यों है? भ्रष्टाचार में नकदी की एक बड़ी भूमिका है।इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि भ्रष्ट नेताओं, नौकरशाहों के पास से करोड़ों-अरबों रुपये की नकदी मिलती ही रहती है।

आज का विचार

अँधेरे से मत डरो, सितारे अँधेरे में ही चमकते हैं

भारत संवाद

राशिफल

मेघ राशि: करियर: आज का दिन अच्छा रहेगा. कार्यक्षेत्र में माहौल अनुकूल रहेगा. विरोधी भी सहयोग करेंगे. बिजनेस: किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, जो आगे चलकर लाभ देगा.धन: आर्थिक दृष्टि से दिन सकारात्मक रहेगा. लाभ के योग हैं. शिक्षा: विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करें, सफलता मिल सकती है.

वृषभ राशि : करियर: कार्यक्षेत्र में लाभ के योग हैं. पुराने कार्य को छोड़ सकते हैं. बिजनेस: किसी नए कार्य का शुभारंभ संभव है, जिससे आर्थिक स्थिति सुधरेगी. धन: पारिवारिक खरीदारी में खर्च हो सकता है.शिक्षा: पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी, सफलता मिलेगी.

मिथुन राशि: करियर: कार्य में अस्थिरता रहेगी. बाहरी यात्रा संभव है, पर सफलता संदिग्ध.बिजनेस: बने काम बिगड़ सकते हैं, सतर्क रहना जरूरी है. धन: खर्च बढ़ सकते हैं, फिजूलखर्ची से बचें.

कर्क राशि: करियर: अत्यधिक परिश्रम करना पड़ेगा. थकान और तनाव संभव.बिजनेस: बड़े बदलाव से बचें, फिलहाल स्थिरता ही लाभकारी होगी. धन: सोच-समझकर निर्णय लें. शिक्षा: एकाग्रता की कमी रह सकती है. लव/पारिवारिक: दुखद समाचार मिल सकता है, जिससे मन व्यथित रहेगा. उपाय: शिव जी को जल चढ़ाएं.

सिंह राशि : करियर: रुके हुए कार्य पूरे होंगे. तरक्की के योग हैं. बिजनेस: नई डील या पार्टनरशिप से लाभ हो सकता है. धन: निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है. शिक्षा: विद्यार्थियों को मेहनत का फल मिलेगा. लव/पारिवारिक: धार्मिक आयोजन हो सकता है. परिवार संग यात्रा के योग बनेंगे.

कन्या राशि : करियर: किसी खास कार्य के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है. बिजनेस: व्यापार में नए परिवर्तन का विचार लाभकारी हो सकता है. धन: पैतृक संपत्ति से लाभ संभव है.शिक्षा: पुराने मित्र की मदद से पढ़ाई में लाभ हो सकता

है.लव/पारिवारिक: दिन पारिवारिक दृष्टि से अच्छा रहेगा.

उपाय: गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें.

तुला राशि: करियर: जोखिम भरे फैसले से बचें, कार्य में सतर्कता रखें. बिजनेस: किसी पर अत्यधिक निर्भरता नुकसानदेह हो सकती है. धन: निवेश सोच-समझकर करें. शिक्षा: पढ़ाई में उतार-चढ़ाव रह सकता है.

वृश्चिक राशि:करियर: स्वास्थ्य समस्याएं परेशानी बढ़ा सकती हैं. काम पर असर पड़ेगा. बिजनेस: लेनदेन सावधानी से करें. कानूनी दस्तावेजों की जांच जरूरी है. धन: अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है.

मकर राशि :करियर: कोई शुभ समाचार मिलेगा. कार्य में उन्नति होगी. बिजनेस: प्रॉपर्टी डीलिंग से लाभ होगा. धन: निवेश से लाभ की संभावना है. शिक्षा: एकाग्रता बनी रहेगी, परिणाम अच्छे आएंगे. लव/पारिवारिक: मांतालिक कार्य के योग हैं, परिवार में आनंद रहेगा.

कुंभ राशि : करियर: वाहन चलाते समय सावधानी रखें. कार्य में विवादों से बचें. बिजनेस: निवेश सोच-समझकर करें, हानि के संकेत हैं. धन: किसी अपरिचित को उधार देना हानिकारक होगा. शिक्षा: पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो सकता है.लव/पारिवारिक: पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद संभव है.उपाय: भगवान शिव को नीला पुष्प चढ़ाएं.

मीन राशि : करियर: कार्य में सफलता धीरे-धीरे मिलेगी, यात्रा सफल रहेगी. बिजनेस: व्यापार में बदलाव के योग हैं, विशेषज्ञ की सलाह लें. धन: धन संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी. शिक्षा: छात्रों के लिए दिन अच्छा है. लव/पारिवारिक: लवमेट से तालमेल बेहतर होगा, मतभेद खत्म होंगे. उपाय: मछलियों को आटा खिलाएं.

ज्योतिष सेवा केन्द्र
ज्योतिषाचार्य पंडित अतुल शास्त्री

मताधिकार और नागरिकता का पेचीदा सवाल, मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़े कई सवाल

राजनीतिक प्रयोगशाला में देर-सबेर नागरिकता संशोधन कानून अपनी उपयोगिता निभा सकता है लेकिन न्यायपालिका भी सत्ता का आईना है जिसमें लोकतंत्र की नाव यथार्थ से थोड़ी दूर मगर सुरक्षित दिखाई देती है।बहस के दौरान की गई अदालती टिप्पणियां फैसलों में प्राय विलुप्त हो जाती हैं।देश में कानून का राज है किसी दल विशेष का नहीं।

पा बिहार में मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।इस मामले में विपक्षी दलों की ओर से पैरवी में लगे वकील-सांसद कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी थी कि इस समीक्षा की आड़ में निर्धन, अशिक्षित, दलित और वंचित तबके के लोगों को मतदाता सूची से बाहर करने का षड्यंत्र किया जा रहा है और सत्ताधारी दल के इशारे पर चुनाव आयोग मनमानी कर रहा है।जब चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि मताधिकार के लिए नागरिकता अनिवार्य है और आधार, राशन, चुनाव, पैन कार्ड आदि को नागरिक होने का प्रमाण नहीं माना जा सकता तो न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और जायमल्या बागची ने कहा कि नागरिकता की जांच का काम तो गृह मंत्रालय का है, न कि चुनाव आयोग का।इस पर आयोग की ओर से जवाब दिया गया कि उसे अनुच्छेद 326 के तहत भी अधिकार प्राप्त हैं।फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया है।अब 28 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होगी।पुनरीक्षण प्रक्रिया जारी रखने की हरी झंडी दिखाने के साथ ही शीर्ष अदालत ने इस प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आधार, वोटर, राशन कार्ड आदि दस्तावेजों को मान्य करने का सुझाव देते हुए मतदाता सूची अधिसूचित करने से पहले सभी पक्षों को अवगत कराने का भी निर्देश दिया।यह निर्देश भी दिया कि बिना अवसर दिए किसी का नाम न हटाया जाए।चुनाव आयोग 2003 के बाद



मतदाता बने व्यक्तियों की नागरिकता संबंधी दस्तावेजों की जांच में आधार, राशन या चुनाव कार्ड को प्रामाणिक दस्तावेज नहीं मान रहा था।संवैधानिक संस्था होने के नाते चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के सुझावों-निर्देशों का सम्मान करना ही चाहिए, पर इस बार दुविधा बहुत बड़ी है।पैच इस पहलू में फंसा हुआ है कि मतदाता होने के लिए भारत का नागरिक होना अनिवार्य है और नागरिकता संशोधन कानून के अनुसार नागरिकता के लिए विशेष रूप से 2004 के बाद भारत में पैदा हुए व्यक्ति को यह प्रमाणित करना अनिवार्य है कि जन्म के समय उसके माता-पिता भारत के नागरिक थे/हैं।अथवा दोनों में से एक नागरिक है और ह्यघुसपैठियाह्न नहीं है।यही वह वर्ग है जो पहली बार मतदाता बनेगा।ऐसे में इस कवायद से जुड़े तमाम सवाल केवल बिहार चुनाव और वहां की मतदाता सूची तक ही सीमित नहीं रहेंगे।इसकी गूंज आने वाले चुनावों में भी सुनाई देगी।बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों

के लोगों के नाम आने के संकेतों के बीच इसकी मांग जोर पकड़ रही कि मतदाता सूची सत्यापन का काम पूरे देश में किया जाए।चुनाव आयोग ने ऐसा करने को कहा भी है।सैद्धांतिक रूप से भारतीय नागरिकता जन्म और निवास के आधार पर तय की गई है।संविधान लागू होने के कुछ समय बाद भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 में प्रविधान किया गया कि अगर किसी व्यक्ति का भारत में जन्म हुआ है तो उसे भारत का नागरिक माना-समझा जाएगा।नागरिकता कानून में जनवरी, 2004 से संशोधन किया गया कि 7 जुलाई, 1987 के बाद, किंतु 7 जनवरी, 2004 से पहले भारत में पैदा हुआ व्यक्ति भारत का नागरिक माना-समझा जाएगा, बशर्ते जन्म के समय उसके माता या पिता भारत के नागरिक हों।7 जनवरी, 2004 के बाद जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक तभी होगा, जब उसके माता-पिता भारत के नागरिक हों या दोनों में से एक भारत का नागरिक हो और दूसरा ह्यघुसपैठियाह्न न हो।नागरिकता

कानून को लेकर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1970 उस साल एक अप्रैल से लागू हुआ।1970 से पहले जन्म या मृत्यु का पंजीकरण अनिवार्य नहीं था।इसलिए हर नागरिक के पास जन्म प्रमाण पत्र होना असंभव है।हालांकि 1970 के बाद जन्में तमाम नागरिकों के पास भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा।अधिकांश के पास पासपोर्ट, राशन कार्ड, आधार, पैन और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज तो हैं, लेकिन माता-पिता के जन्म का प्रमाण पत्र नहीं होगा।पासपोर्ट भारतीय नागरिकों को ही जारी किया जाता रहा है, मगर वह भी सिर्फ यात्रा दस्तावेज है।इस बहस में कुछ और सवाल उभरते हैं।देसी-विदेशी महिला (पुरुष) से विवाह का पंजीकरण अभी तक अनिवार्य नहीं है।अनाथ और लावारिस व्यक्तियों की नागरिकता का क्या होगा? एकल या अविवाहित मांओं के बारे में भी सोचना पड़ेगा या नहीं? 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने एबीसी बनाम दिल्ली राज्य जैसे मामले में फैसला

सुनाया था कि अविवाहित मां को अपने बच्चों की संरक्षता के लिए पिता की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी।उसके आदेश में कहा गया था कि जब भी किसी एकल अभिभावक या अविवाहित मां अपने बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करे तो सिर्फ एक हलफनामा पेश किए जाने पर बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाए।इस निर्णय के बावजूद जन्म प्रमाण पत्र के लिए ह्याआनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टमह्न में अभी भी बच्चे के पिता का नाम बताना अनिवार्य है।अन्यथा पंजीकरण संभव नहीं।यदि किसी मामले में मां की उम्र 18 साल से कम (नाबालिग) है तो मौजूदा ह्यसिस्टमह्न सूचना स्वीकार नहीं करता।अगर 2025 में भी जन्म प्रमाण पत्र लेना इतना आसान नहीं तो अनुमान लगाया जा सकता है कि बिहार या बंगाल में वोट बनवाना कितना मुश्किल काम हो सकता है।राजनीतिक प्रयोगशाला में देर-सबेर नागरिकता संशोधन कानून अपनी उपयोगिता निभा सकता है, लेकिन न्यायपालिका भी सत्ता का आईना है, जिसमें लोकतंत्र की नाव यथार्थ से थोड़ी दूर, मगर सुरक्षित दिखाई देती है।बहस के दौरान की गई अदालती टिप्पणियां फैसलों में प्रायः विलुप्त हो जाती हैं।देश में कानून का राज है, किसी दल विशेष का नहीं।इसलिए कानून का पालन और न्याय व्यवस्था में अटूट आस्था बनाए-बचाए रखना जरूरी है।मताधिकार के लिए नागरिकता अनिवार्य तो है, लेकिन चुनावी फायदे के लिए कानून को राजनीतिक अखाड़ा बनाना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं होगा।

डिजिटल-क्रांति से ही नकली नोटों पर नियंत्रण संभव

ललित गर्ग

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा हाल ही में जारी एक चौंका देने वाली रिपोर्ट ने न केवल अर्थव्यवस्था को, बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा और नागरिकों की जागरूकता को भी झकझोर कर रख दिया है।आरबीआई के गवर्नर द्वारा संसदीय समिति में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2024-25 में 500 रुपए के लगभग 1.8 लाख नोट नकली पाए गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 37 प्रतिशत अधिक हैं।यह संख्या किसी सामान्य अपराध की नहीं, बल्कि राष्ट्र के विरुद्ध एक षड्यंत्र की कहानी कहती है।जो यह दर्शाता है कि कालाबाजारी करने वाले राष्ट्र विरोधी तत्व देश में मुद्रा की मांग का गलत फायदा उठा रहे हैं।विडंबना यह है कि राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा नोट में इस्तेमाल होने वाले आयातित कागज और नकली नोट छापने में शामिल ऑपरेटरों पर लगातार कार्रवाई हो रही है।जबकि 2016 में नोटबंदी के ऐतिहासिक निर्णय के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि भ्रष्टाचार, कालेधन और नकली नोटों के खिलाफ लड़ाई उनकी प्राथमिकताओं में है।नोटबंदी केवल एक आर्थिक सुधार नहीं, बल्कि डिजिटल अर्थव्यवस्था की नींव रखने वाला साहसी एवं युगांतरकारी कदम था।आज भारत को सिर्फ बाहरी सीमाओं पर नहीं, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी एक युद्ध लड़ना पड़ रहा है, नकली मुद्रा के खिलाफ, भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ और राष्ट्रविरोधी मानसिकता के खिलाफ।इसमें विजय तभी संभव है, जब हम सब डिजिटल भारत के निर्माण में सहभागी बनें।नकली मुद्रा का मुद्दा केवल एक आर्थिक अपराध नहीं है।यह एक



प्रकार का आर्थिक आतंकवाद है, जिसका उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करना, महंगाई को बढ़ाना, काले धन को बढ़ावा देना और आतंकवाद को वित्त पोषण देना है।ये नकली नोट अधिकतर सीमापार से संचालित तंत्रों द्वारा भारत में भेजे जाते हैं, जो भारत की राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विकास और आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं।इस तरह राष्ट्र के विरुद्ध षड्यंत्र, साजिश एवं बड़े खतरों को अंजाम दिया जा रहा है।क्योंकि नकली नोट बाजार में असली नोटों के साथ मिलकर मुद्रा व्यवस्था को प्रभावित करते हैं।आम नागरिक अनजाने में इन्हें ले लेता है और आर्थिक नुकसान उठाता है।यह काले धन और आतंकवाद को पोषित करता है।नकली नोट सरकारी योजनाओं की नियक्षता और वितरण प्रणाली को भी प्रभावित करते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी की डिजिटल क्रांति न केवल नकली नोटों को नियंत्रित करने का बल्कि राष्ट्र-विरोधी तत्वों को नेस्तनाबूद करने का सशक्त माध्यम है।यह मोदी की दूरदृष्टि एवं नये भारत-विकसित भारत के विजन की विजय है, उनके ही विचारों में डिजिटल लेन-देन केवल तकनीक नहीं, यह राष्ट्र निर्माण का माध्यम है।आज के भारत की अर्थव्यवस्था एक निर्णायक दौर से गुजर रही है।डिजिटल ग्राम योजना, ई-गवर्नेंस, डिजिटल साक्षरता अभियान यानी तकनीक को गाँव और गरीब तक पहुंचाने की पहल है।एक ओर

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश डिजिटल इंडिया की ओर तेजी से बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर नकली नोटों की बाढ़ एक अदृश्य आतंकवाद बनकर देश की अर्थव्यवस्था, समाज और सुरक्षा को चुनौती दे रही है।निस्संदेह, हाल के वर्षों में, भारत ने नकली नोटों की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने व काले धन पर रोक के लिये डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिये अपनी स्थिति खासी मजबूत की है।सरकार की सोच है कि काले धन पर रोक लगाने के लिए नगद लेन-देन को हतोत्साहित किया जाए।

इस संकट की घड़ी में डिजिटल लेन-देन एक बड़ी राहत और समाधान बनकर उभरा है।यूपीआई, भीम मोबाइल वॉलेट्स, नेट बैंकिंग और कार्ड पेमेंट्स जैसे साधन नकली नोटों की समस्या को जड़ से समाप्त करने में सहायक हो सकते हैं।डिजिटल लेन-देन के लाभ ही लाभ है, पूर्ण पारदर्शिता यानी हर लेन-देन का डिजिटल रिकॉर्ड होता है, जिससे भ्रष्टाचार में कमी आती है।कर चोरी, हवाला, और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी काली प्रवृत्तियाँ समाप्त होती है।नकली मुद्रा की संभावनाओं पर विराम लगता है, जिससे राष्ट्र-विरोधी तत्वों के षड्यंत्र एवं साजिशें नाकाम होती है।लेन-देन संकेतों में पूरा होता है और उनमें सरलता भी रहती है।पासवर्ड आधारित सुरक्षा व्यवस्था से लेन-देन सुरक्षित रहता है।सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ लाभार्थियों तक पहुंचता है, पैसा सीधे उनके खातों में पहुंचता है, बिचौलियों की भूमिका

समाप्त होती है।जिससे भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने हर मंच पर डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने की बात कही है।उन्होंने गाँव-गाँव जाकर लोगों को मोबाइल बैंकिंग, क्यूआर कोड, और कार्ड से भुगतान की शिक्षा देने की मुहिम चलाई है।इसका असर यह है कि आज भारत यूपीआई ट्रांजैक्शन में दुनिया में नंबर 1 है।डिजिटल इंडिया गरीब को ताकत देता है, मिडल क्लास को सुविधा देता है और राष्ट्र को मजबूती देता है।भारत की असली शक्ति अब डिजिटल प्रचलन बन रही है, जहाँ एक बटन से करोड़ों का ट्रांजैक्शन सुरक्षित होता है।मोदी की डिजिटल क्रांति ने भारत को इक्कीसवीं सदी की आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में मजबूत आधार दे दिया है।हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस डिजिटल युद्ध में सहभागी बनें, नकली नोटों को ना कहें, डिजिटल लेन-देन को अपनाएं।यही राष्ट्रभक्ति है, यही समय की माँग है।संदिग्ध नकदी की सूचना तुरंत संबंधित एजेंसियों को दें।नकली नोटों की पहचान करना सीखें और दूसरों को भी जागरूक करें।निश्चित ही जहाँ नकली नोट देश की आत्मा को खोखला करते हैं, वहीं डिजिटल मुद्रा राष्ट्र की नींव को मजबूत करती है निस्संदेह, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई ने भारत के आर्थिक लेन-देन तंत्र में क्रांति ला दी है।भुगतान के तमाम विकल्पों ने भारतीय नागरिकों के आर्थिक व्यवहार को बहुत आसान बना दिया है।हालांकि, अभी भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो डिजिटल माध्यम से लेन-देन में परहेज करते हैं।निस्संदेह, नकदी पर उनकी निर्भरता का मूल कारण डिजिटल शिक्षा का अभाव ही है।साथ-ही-साथ डिजिटल भुगतान से जुड़े घपल्ले एवं घोटाले भी है।साथ ही इसके कारणों में भ्रष्टाचार और कर चोरी की नीयत भी शामिल है।ऐसे में सरकार को डिजिटल खाई को पाटने की दिशा में रचनात्मक पहल करनी चाहिए।

नॉर्थ कोरिया,रूस और चीन की जुगलबंदी, बढ़ गई डोनाल्ड ट्रंप की बेचैनी

संजीव ठाकुर

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति पद की ताजपोषी के साथ-साथ डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूस यूक्रेन युद्ध के युद्ध को विराम तो नहीं दे पाए किंतु युद्ध की आग को और भड़का दिया है।उधर परमाणु संपन्न देश चीन नॉर्थ कोरिया और रूस की त्रिगुटीय जुगलबंदी ने अमेरिका सहित नाटो यूरोपीय देश और यूक्रेन की नौद उड़ा दी है।उल्लेखनीय की नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के आपस के कड़वे रिश्ते के बीच अमेरिका का साउथ कोरिया को लेकर काफी हस्तक्षेप है जिसे नॉर्थ कोरिया कई दशक से पसंद नहीं करता आया है।संयुक्त राष्ट्र संघ और एमनेस्टी इंटरनेशनल की भूमिका निरर्थक हो चुकी है वैसे भी संयुक्त राष्ट्र इस अमेरिका तथा यूरोपीय देशों की कठपुतली बन चुका है।क्या मानवीय संवेदनाओं की आशाएँ निमृल साबित हो रही हैं।वैश्विक शांति और अमन की कल्पनाओं से परे वैश्विक युद्ध की आशंका में उत्तर कोरिया ने भी अपना मोर्चा खोल दिया है।ताजा ताजा घटनाक्रम में रूस के विदेश मंत्री लावरोव उत्तर कोरिया के दौरे पर जाकर वहाँ के समकक्ष चोई सॉन सॉंग से उत्तर कोरिया के शहर पूर्वी वॉनसान में अत्यंत महत्वपूर्ण मीटिंग की है।रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने उत्तरी कोरिया के तानाशाह नेता किम जोंग उन से भी मुलाकात कर रूस को यूक्रेन और अमेरिका के खिलाफ समर्थन देने की बात रखी जवाब में उत्तरी कोरिया के तानाशाह नेता किम जोंग उन ने रूस को अमेरिका यूरोप और यूक्रेन के खिलाफ निशर्त खुला समर्थन देने की घोषणा कर दी है।गौरतलब है कि उत्तरी कोरिया पिछले कई महीनो से मिसाइल का परीक्षण कर साउथ कोरिया अमेरिका तथा यूरोपीय देशों को सीधा-सीधा संदेश दिया है कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के संबंधों के बीच किसी देश के हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।उत्तर

कोरिया की आधिकारिक न्यूज एजेंसी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के अनुसार दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच अब तनाव बढ़ने लगा हैह्नु उधर उत्तर कोरिया के बढ़ते परमाणु कार्यक्रम के जवाब में अमेरिका दक्षिण कोरिया व जापान त्रिपक्षीय त्रिपक्षी संधियाँ और सैनिक अभ्यास का विस्तार तथा फिर से बहाली कर रहे हैं।तीनों देशों ने उत्तर कोरिया के रूस और चीन को समर्थन देने के और परमाणु परीक्षणों के खिलाफ दक्षिण कोरिया प्रायद्वीप के पास अमेरिकी परमाणु सक्षम बम वर्षकों के साथ संयुक्त हवाई अभ्यास किया है।उल्लेखनीय है कि तीनों देशों के सैन्य प्रमुखों ने एक गंभीर बैठक कर उत्तर कोरिया से क्षेत्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाली सभी गैर कानूनी गतिविधि बंद करने का आह्वान किया है वैसे भी उत्तर कोरिया अमेरिका के नेतृत्व में दक्षिण कोरिया और जापान के इस युद्ध अभ्यास को उत्तर कोरिया के खिलाफ होने वाले हमले का पूर्व अभ्यास मानता है।उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर बड़े हमले की चेतावनी भी दे डाली है।इन परस्थितियों में विश्व में चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध तथा इसराइल हमास लेबनान ईरान युद्ध के अलावा उत्तर कोरिया ने हमले की धमकी देकर एक नये युद्ध का मोर्चा खोल दिया हैह्नु यह तो सर्व विदित है कि उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग-उन एक सनकी तानाशाह है और अमेरिका पर परमाणु युद्ध के हमले की गाह-बगाह धमकियाँ भी दिया करता हैह्नु उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया की किसी भी हिमाकत पर उस पर हमला कर सकता हैह्नु उधर रूस यूक्रेन युद्ध को ढाई वर्ष पूरे हो चुके है कई प्रभावशाली प्रयासों के बाद भी युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है रूस के क्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के क्लादिमीर जेलेन्स्की हास्य कलाकार होने के बावजूद यूक्रेन के लिए त्रासदी के नायक बन गए हैं।

फास्ट ट्रेक

थाना चिल्ह पुलिस द्वारा बहला फुसला के भगाने व धमकी के अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना चिल्ह, जनपद मीरजापुर पर दिनांक: 09.07.2025 को एक व्यक्ति द्वारा नामजद अभियुक्त के विरुद्ध वादी की नाबालिक पुत्री को बहला झगड़सला के भगाने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गई । उक्त के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चिल्ह पर मु0अ0स0-176/2025 धारा 137(2),87,351(4) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई ।सोमने बर्मा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर द्वारा उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में थाना प्रभारी चिल्ह के अभियुक्त की गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए । उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना स्थानीय पर पंजीकृत उपरोक्त अभियोग में सुरागसंगी पतारसी एवं अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में दिनांक: 15.07.2025 को उप-निरीक्षक सुरेश राम मय पुलिस टीम द्वारा प्राप्त मुखबिर सूचना के आधार पर थाना चिल्ह क्षेत्र से नामजद अभियुक्त प्रिंस कुमार पुत्र हरिराम प्रजापति निवासी ग्राम बालापुर्, थाना बड़हरिया जनपद सिवान बिहार को अंतर्गत धारा 137(2),87, 351(4) बीएनएस में गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए मा0न्यायालय/जेल भेजा गया ।

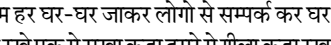
कार्य का जिलाधिकारी ने निरीक्षण अविलम्ब कार्य पूर्ण करने का दिया निर्देश, जल निगम के अधिकारियों को लगाई फटकार

मीराजापुर, जल जीवन मिशन/जल निगम नगरीय द्वारा लालडिग्री पुलिस के बगल में विगत 40 दिनों से सीवर/पाइप बिछाने के कार्य हेतु बड़ा गड्ढा खोदकर कार्य में लेट लतीफी होने तथा वहां वासियों के द्वारा जिलाधिकारी से शिकायत के पश्चात जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने आज लालडिग्री पहुंचकर मौके का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वहां के निवासियों के द्वारा बताया गया कि सीवर अथवा पाइप बिछाने/कनेक्शन के नाम पर लगभग 12 फीट लम्बाई व 07 से 08 फीट की गहराई में गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया है जिससे आने जाने में यातायात प्रभावित हो रहा है तथा आस पास के दुकानदारों को भी काफी परेशानी हो रही है। जिलाधिकारी ने निरीक्षणोपरान्त जल निगम नगरीय के अधिशासी अधिकारी को कड़ी फटकार लगाते हुए अविलम्ब कार्य पूर्ण कर सड़क मरम्मत सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया तो वहीं पास में ही पाइप कनेक्शन के नाम पर लगभग 05 फीट गहरा गड्ढा अलग से खोदे जाने पर अवर अधिशासी जल निगम नगरीय अधिनाश मौर्या को कड़ी फटकार लगाते हुए चेतावनी दी कि एक सप्ताह के अन्दर कनेक्शन कार्य पूर्ण कर गड्ढा पाटते हुए सड़क मरम्मत सुनिश्चित कराएं अन्यथा एक सप्ताह में कार्य पूर्ण न होने पर निलम्बन की कार्यवाही की जाएगी। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि वर्षा के मौसम में सड़क की खुदाई न करने के निर्देश के उपरान्त भी गड्ढा खोदा गया जो घोर लापरवाही का द्योतक है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि वर्षा के मौसम को देखते हुए सड़क को पर कहीं गड्ढा आदि की खोदाई न की जाए ताकि यातायात सुचारु रूप से संचालित रहे। इस अवसर पर लालडिग्री में एक होटल/रेस्टोरेंट के बगल की गली में भी नगर पालिका गड्ढा खोदाई करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल कार्य पूर्ण करारक गलियों/नालियों की मरम्मत कराने का निर्देश दिया गया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वि०/रा० अजय कुमार सिंह, नगर मजिस्ट्रेट विनीत उपाध्याय, उप जिलाधिकारी सदर गुलाब चन्द्र, अधिशासी अधिकारी नगर गोवा लाल सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।

गीला कूड़ा सुखा कूड़ा अलग ही शहर को साफ-स्वच्छ बना सकता है

भारत संवाद

प्रयागराज नगर निगम की ये पहल ही शहर को साफ-सुच्छ बनाने का पहला कदम है। इसी तहत श्रुति बेस्ट मैनेजमेंट की टीम अलग अलग अपार्टमेंट, सोसाइटी, शहर के अलग अलग मोहल्ले में टिम हर घर-घर जाकर लोगों से सम्पर्क कर घर में दो डस्टबीन रखे एक में सुखा कुड़ा दूसरे में गीला कुड़ा रखे।



अपना कचरा सही जगह डालें। अपने घर में दो डस्टबीन रखें।

उससे दूर और अपने यहां काम करने वाली या वाले को घर का जो भी औप उपनये का जगह न रख कर अलग रखे और उससे इधर-अधर न पेक सोसाइटी के निचे रखे डो डस्टबीन में अलग अलग रखे जिसे गाडी के सफाई कर्मी उठा कर ले जातेये को कुछ काम करने वाली पालिथिन में बांध कर किसी कोने में या डस्टबीन में डाल देती आप उन बताये सुखा कुडा गिला कुडा अलग अलग पैक कर डस्टबीन में डाले आप सच्ची सम्मानित लोग नगर निगम के अधिबान में अपना सहयोग करे और शहर को नम्बर वन के साथ प्रयागराज की गरिमा को स्वच्छता के प्रति बनाये रखे पालिथिन का बहिष्कार कर कपडे के झोले का प्रयोग करे स्वच्छता को मजबूरी नही संस्कार में लाये और शहर को स्वच्छ बनाये रखने के लिये विशेष ध्यान रखने के लिये दुकानजी ने जोनल अधिकारी विकास सेन से चर्चा करते हुए स्वच्छता बनाये रखने के लिए हर प्रकार से सहयोग करने के लिए कहा

जिलाधिकारी ने कोन ब्लॉक के ग्राम हरसिंहपुर

में सम्भावित बाढ़ के दृष्टिगत किया निरीक्षण

किनारे कई गांव होने के कारण बाढ़ की सम्भावना बनी रहती है। गंगा नदी का चेतानवी बिन्दु 76.724 मीटर है जबकि वर्तमान में गंगा नदी का जल स्तर 74 मीटर पर चल रहा है। उन्होंने बताया कि यमुना और बेतवा नदियों में जल स्तर वृद्धि होने के कारण तीनों सेंटमीटर प्रतिघण्टा से नदी के जल स्तर में वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि बाढ़ के दृष्टित बनाई गई टीमें लगातार निगरानी कर रहें सभी लोगों को अवगत भी जारी कर दिया गया है बाढ़ चैकिया व आपदा राहत शिविर को तैयार रखने का निर्देश दिया गया, सम्बन्धित उप जिलाधिकारी व जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा बाढ़ शिविरों चैकिया का निरीक्षण किया जा रहा है जिलाधिकारी द्वारा हरसिंहपुर, मल्लेपुर में गंगा तट, तलतों में बाढ़ चैकी व मवैया में बाढ़ राहत को बाढ़ निरीक्षण जायज लिया गया



चीन में जिनपिंग से मिले जयशंकर, कहा- रिश्ते सुधर रहे

राहुल गांधी बोले- भारत की विदेश नीति को बर्बाद कर रहे जयशंकर

एजेंसी

बीजिंग, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। इस मुलाकात पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री भारत की विदेश नीति को बर्बाद कर रहे हैं। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जिनपिंग से मुलाकात की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा- बीजिंग में एससीओ के विदेश मंत्रियों के साथ

मैंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। उन्हें भारत-चीन के बीच रिश्तों में हुई प्रगति के बारे में बताया। जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात की जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चीन पहुंचे हैं। इससे पहले जयशंकर ने विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की थी। इस बैठक में उन्होंने दोनों देशों के बीच स्थिर और रचनात्मक संबंध बनाने की जरूरत पर जोर दिया। जयशंकर ने कहा कि सीमा से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, लोगों



के बीच संपर्क को सामान्य बनाना चाहिए और व्यापार में आ रही रुकावटें

को हटाने पर काम करना चाहिए। उन्होंने विश्वास जताया कि आपसी सम्मान और समझदारी के आधार पर भारत-चीन संबंध सकारात्मक दिशा में बढ़ सकते हैं। चीनी विदेश मंत्री से व्यापार और पर्यटन पर चर्चा बीजिंग में हुई बैठक के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने अपने चीनी समकक्ष वांग यी से व्यापार और पर्यटन को लेकर भी अहम मुद्दे उठाए। उन्होंने चीन द्वारा लगाए गए एक्सपोर्ट कंट्रोल और व्यापारिक प्रतिबंधों को लेकर चिंता जताई। जयशंकर ने साफ कहा कि चीन

को ऐसे कदमों से बचना चाहिए जो भारत के उत्पादन क्षेत्र (मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर) को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने भारत और चीन के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने यात्रा को आसान बनाने, सीधी उड़ानों (डायरेक्ट फ्लाइट्स) को फिर से शुरू करने और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने की आवश्यकता बताई। उनका मानना है कि इससे दोनों देशों के बीच आपसी समझ और भरोसा बढ़ेगा। एससीओ बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस.

जयशंकर ने आतंकवाद को लेकर भारत का स्पष्ट रुख दोहराया। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की स्थापना का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ से मुकाबला करना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी सदस्य देशों को हज्जोरो टॉलरेंसह (कटई बर्दाश्त न करने) की नीति पर मजबूती से टिके रहना चाहिए। इसके साथ ही जयशंकर ने चीन द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने के फैसले का स्वागत किया। यह यात्रा पिछले पांच वर्षों से बंद थी, और इसका दोबारा शुरू होना दोनों देशों के बीच भरोसे और धार्मिक-सांस्कृतिक संबंधों

के लिए एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। जयशंकर बोले- भारत-चीन के संबंध सुधर रहे जयशंकर और वांग यी के बीच सोमवार को द्विपक्षीय बैठक हुई। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को बीजिंग में चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से मुलाकात की थी। जयशंकर ने मौजूदा अंतरराष्ट्रीय हालात को जटिल बताया और कहा कि भारत और चीन जैसे बड़े पड़ोसी देशों के बीच खुलकर बातचीत बेहद जरूरी है। उन्होंने चीनी उपराष्ट्रपति को बताया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के फिर से शुरू होने को भारत में बेहद सराहा गया है।

यूक्रेन की प्रधानमंत्री बन सकती हैं यूलिया स्विरीडेंको

मौजूदा पीएम को रक्षा मंत्री बनाया जाएगा, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुद सिफारिश की

एजेंसी

कीव, यूलिया स्विरीडेंको यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री बन सकती हैं। खुद राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने उनकी सिफारिश की है। यूलिया, जेलेंस्की की करीबी मानी जाती हैं। वह 2020 से पीएम पद पर काबिज डेनिस श्मिहाल की जगह लेंगी। जेलेंस्की ने सोमवार को एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि वे सरकार में जरूरी बदलाव चाहते हैं। हालांकि यूलिया का डट बनाना संसद की मंजूरी पर निर्भर करता है। जेलेंस्की की पार्टी 'सर्वेंट ऑफ पीपल' 2019 से 254 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत में है। ऐसे में माना जा रहा है कि वे देश की



अगली पीएम बनेंगी। रिपोर्ट के मुताबिक यूलिया के प्रधानमंत्री बनाए जाने को लेकर आज संसद में चर्चा हो सकती है। यूलिया को नए पीएम बनाए जाने की कोशिश को लेकर विपक्षी

पार्टियां नाराज हैं। उनका कहना है कि उप-प्रधानमंत्री को ही प्रधानमंत्री बनाना कोई बड़ा बदलाव नहीं है, बल्कि बस चेहरों की अदला-बदली है। कुछ विरोधियों का यह भी आरोप है कि

जेलेंस्की ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि वह अपनी सत्ता और मजबूत कर सकें। उन्होंने जेलेंस्की पर अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने सोमवार शाम के संबोधन में यह भी घोषणा की कि वे मौजूदा प्रधानमंत्री डेनिस श्मिहाल को रक्षा मंत्री बनाना चाहते हैं। जेलेंस्की ने कहा कि श्मिहाल का अनुभव इस पद के लिए बेहद अहम और कीमती होगा। उन्होंने बताया कि इस समय देश के सबसे अधिक संसाधन और जिम्मेदारियां रक्षा मंत्रालय से जुड़ी हैं, इसलिए इस क्षेत्र में कुशल नेतृत्व की जरूरत है। अगर संसद इस बदलाव को मंजूरी देती है, तो श्मिहाल वर्तमान रक्षा

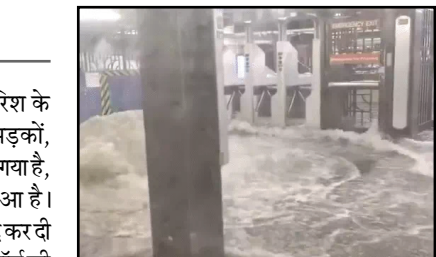
मंत्री रुस्तम उमेरोव की जगह लेंगे। जेलेंस्की ने बताया कि उमेरोव को अमेरिका में यूक्रेन का राजदूत बनाने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें अमेरिका के साथ संबंधों में और तेजी और यूक्रेन के रक्षा क्षेत्र के प्रबंधन में नए कदमों की जरूरत है। यूक्रेन और अमेरिका के बीच फरवरी में 50% रेयर अर्थ मटेरियल (दुर्लभ खनिज) को लेकर डोल हुई थी। इनमें ग्रेफाइट, यूरेनियम, टाइटैनियम, लिथियम समेत कई बेशकीमती और दुर्लभ खनिज शामिल थी। उनका इस्तेमाल टेस्ला की कारों से स्पेसएक्स के रॉकेट तक, होवित्जर तोप से मोबाइल की चिप तक में होता है।

न्यूयॉर्क में भारी बारिश से बाढ़, सड़क-मेट्रो स्टेशन डूबे

इमरजेंसी का ऐलान, मदद के लिए रेस्क्यू टीम तैनात

एजेंसी

न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क शहर में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। सड़कों, मेट्रो स्टेशनों और गैस स्टेशनों पर पानी भर गया है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मैनहट्टन में मेट्रो सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गईं। कुछ इलाकों में 7 इंच तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। बाढ़ के कारण कुछ फ्लाइटें भी रद्द कर दी गईं, जिससे यात्रियों को घंटों ट्रेफिक जाम में फंसे



रहना पड़ा। राष्ट्रीय मौसम सेवा (एनडब्ल्यूएस) ने न्यूयॉर्क के पांच इलाकों मैनहट्टन, ब्रॉक्स,

ब्रुकलिन, क्वींस और स्टेटन आइलैंड के लिए बाढ़ की चेतावनी जारी की है। अनुमान है कि शहर का लगभग 16% हिस्सा बाढ़ से प्रभावित है। न्यू जर्सी के गवर्नर फिल मफ्फी ने मंगलवार को राज्य में आपातकाल (इमरजेंसी) की घोषणा की और राहत व बचाव कार्यों के लिए टीमें तैनात की गई हैं। हालांकि, अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि बारिश रातभर जारी रह सकती है और अचानक

बाढ़ की संभावना बनी हुई है। न्यूयॉर्क सिटी इमरजेंसी मैनेजमेंट ने खासतौर पर बेसमेंट अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और रात के समय बिना चेतावनी के आने वाली बाढ़ के लिए तैयार रहने को कहा है। वहीं लोगों को सलाह दी गई है कि वे फोन, चर्च और जरूरी सामानों से भरा बैग अपने पास रखें और किसी भी स्थिति में ऊंचे स्थान पर जाने के लिए तैयार रहें। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में आपातकालीन टीमें अलर्ट पर हैं और प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की मदद के लिए तैनात की गई हैं। बारिश के कारण कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन गई है और शहर के प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है।

यमन में निमिषा प्रिया की फांसी की सजा फिलहाल टली



एजेंसी

नई दिल्ली: यमन के स्थानीय अधिकारियों ने 16 जुलाई 2025 को निमिषा प्रिया की निर्धारित फांसी की सजा स्थगित कर दी है। भारत सरकार जो इस मामले की शुरूआत से ही हर संभव सहायता प्रदान कर रही है, उस ने हाल के दिनों में निमिषा प्रिया के परिवार को दूसरे पक्ष के साथ आपसी सहमति से समाधान निकालने के लिए और समय देने के लिए भी लगातार प्रयास किए हैं। सूत्रों के मुताबिक मामले की संवेदनशीलता के बावजूद भारतीय अधिकारी स्थानीय जेल अधिकारियों और अभियोजन कार्यालय के साथ नियमित संपर्क में रहे हैं, जिसके कारण यह स्थगन संभव हो पाया है. इससे पहले भारत सरकार ने केरल की नर्स की फांसी रोकने के लिए अंतिम प्रयास किया था.फांसी स्थगित करने की औपचारिक अपीलइस संबंध में सरकार ने यमन के अभियोजन महानिदेशक से निमिषा प्रिया की फांसी स्थगित करने की औपचारिक अपील की थी. बता दें कि निमिषा को यमन के एक नागरिक की हत्या के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई है.

यमन में 16 जुलाई 2025 को केरल की नर्स निमिषा प्रिया की निर्धारित फांसी की सजा स्थगित कर दी गई है.

2012 में नर्स के तौर पर यमन चली गई थीं और उनके पति टॉमी भी यमन में रहते थे. जानकारी के मुताबिक उन्होंने तलाल के साथ मिलकर एक क्लिनिक शुरू की थी. इस बीच उनके पति और बेटी भारत लौट आए, लेकिन यमन में युद्ध छिड़ जाने के कारण निमिषा उनके साथ नहीं आ सकीं, जिससे वह कथित तौर पर उस यमनी नागरिक तलाल के जाल में फंस गईं.

तलाल को इंजेक्शन देकर किया बेहोश

तलाल ने निमिषा और एक अन्य यमनी महिला का कथित तौर पर गंभीर शारीरिक और मानसिक शोषण किया और उनके पासपोर्ट भी जब्त कर लिए. हताशा होकर निमिषा और उस यमनी महिला ने उसे एक इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया और अपने पासपोर्ट छीनकर भागने की कोशिश की. हालांकि, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और जेल में डाल दिया.बाद में तलाल का शव उनके क्लिनिक में मिला, जिसके कारण उन पर हत्या का आरोप लगाया गया और बाद में मुकदमा चलाया गया.

राजस्थान में भारी बारिश से 16 की मौत ,यूपी में उद्घाटन से पहले 4 पुलों की सड़कें बही

लखनऊ, कानपुर, बरेली समेत 15 शहरों में तेज बारिश के कारण जलभराव-बाढ़ के हालात हैं। प्रदेश के कई बांध और फ्लो होने लगे हैं। सोमवार को ललितपुर के गोविंद सागर बांध के 17 गेट खोले गए। चित्रकूट में उद्घाटन से पहले 51 करोड़ से बने 4 पुलों की एग्रोच सड़कें बह गईं। एजेंसी

नई दिल्ली ,राजस्थान में भारी बारिश के चलते बाढ़ के हालात हैं। प्रदेश में बरसात के कारण हुए अलग-अलग हादसों में 24 घंटों में 16 लोगों की मौत हो गई। सोमवार को कोटा में प्रदेश में सबसे ज्यादा 198 बारिश हुई। यहां कोटा बैराज के 12 गेट खोले गए हैं। मध्य प्रदेश में मानसून जमकर बरस रहा है। नर्मदा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जबलपुर, रीवा समेत 10 जिलों में एक सप्ताह से लगातार बारिश जारी है। इन जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। सोमवार को रघोपुर के कई इलाके और गांव पानी से घिरे रहे। मकान-

इस साल के अंत में होने वाले राज्य चुनावों से पहले घोषित इस फैसले को सत्तारूढ़ एनडीए सरकार द्वारा बिहार में बढ़ती बेरोजगारी और रोजगार सृजन पर कथित निष्क्रियता को लेकर विपक्ष की आलोचना का जवाब देने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। एजेंसी

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार

मध्य प्रदेश में नर्मदा खतरे के निशान से ऊपर



दुकानों से लेकर अस्पताल तक में पानी भर गया। हिमाचल प्रदेश में बीते 24 दिन में 105 लोगों की मौत बारिश से जुड़ी घटनाओं में हो चुकी हैं। राज्य की 200 से ज्यादा सड़कें अभी भी बंद हैं। मनाली-चंडीगढ़ हाईवे पिछले 3 दिन से रोजाना लैंडस्लाइड के चलते बंद हो रहा है।

यूपी के ललितपुर में गोविंद

काशी में गंगा में नाव संचालन पर पूरी तरह से रोक

उत्तर प्रदेश के काशी में गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जल पुलिस ने नावों के संचालन पर रोक लगा दी है। अभी तक नाविक गंगा आरती के समय नाव में श्रद्धालुओं को बैठाकर आरती दिखाते थे, अब इस पर भी रोक लगा दी गई है राजस्थान में मानसून के इस सीजन बारिश से जुड़ी घटनाओं में अबतक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें पानी में डूबने, बिजली गिरने, बिल्डिंग गिरने और कटेंट लगने से हुई मौत शामिल हैं। चित्तौड़गढ़ में 4, , कोटा में 4, प्रतापगढ़ में 3, चूरू में 2, राजसमंद में 1, भरतपुर में 1 और पाली में 1 की मौत हुई है। तुरक के सुजानगढ़ में श्मशान घाट में पानी भरा, अस्थाई पुल से शव अंदर लाए जा रहे। राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ भोजलाई बास में चापटिया श्मशान घाट में बारिश का पानी भर गया है।

अगले 5 साल में युवाओं को मिलेगी 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार

बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा फैसला



मुख्यमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में इसी

तरह की घोषणा की थी, जिसमें उन्होंने

यह भी दावा किया था कि 2005 से 2020 के बीच बिहार में आठ लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियाँ दी गईं। कुमार ने पोस्ट में कहा, अगले पाँच वर्षों (2025 से 2030) के लिए, हम एक करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरियाँ और रोजगार के अवसर प्रदान करके इस लक्ष्य को दोगुना करने का लक्ष्य रख रहे हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, निजी क्षेत्र, खासकर औद्योगिक क्षेत्रों में, नई नौकरियाँ और रोजगार के अवसर भी पैदा किए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा, इसके लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया जा रहा है।

किसी न किसी को तो ज़िम्मेदार ठहराया ही जाना चाहिए

पहलगाम आतंकी हमले पर बोले उमर अब्दुल्ला

उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह मुश्किल नहीं है कि 26 लोगों की जान चली जाए और हमारी तरफ से कोई प्रतिक्रिया न आए। अब जब हम जानते हैं कि सुरक्षा और खुफि या तंत्र में कोई चूक हुई है, तो किसी न किसी को तो ज़िम्मेदार ठहराया ही जाना चाहिए। एजेंसी

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के लिए किसी न किसी को तो ज़िम्मेदार ठहराया ही जाना चाहिए। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। यह हमला धार्मिक भेदभाव के आधार पर किया गया था। मुख्यमंत्री उमर ने इस घातक हमले की जवाबदेही तय करने की माँग करते हुए प्रत्कारों से कहा कि इस विफलता के लिए कौन ज़िम्मेदार है? अगर यह खुफि या तंत्र की विफलता है, तो इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? उमर अब्दुल्ला ने कहा कि



यह मुश्किल नहीं है कि 26 लोगों की जान चली जाए और हमारी तरफ से कोई प्रतिक्रिया न आए। अब जब हम जानते हैं कि सुरक्षा और खुफि या तंत्र में कोई चूक हुई है, तो किसी न किसी को तो ज़िम्मेदार ठहराया ही जाना चाहिए। 22 अप्रैल को, दक्षिण कश्मीर के मनोरम शहर पहलगाम में आतंकवादियों ने पर्यटकों के एक समूह पर हमला किया। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7 मई की सुबह ऑपरेशन सिंसरू शुरू किया और पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओजेक) में आतंकी ढाँचों पर हमला किया।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं अखिलेश द्विवेदी पुत्र राम सेवक द्विवेदी एलजी 2 सुखरावती तलवार अपार्टमेंट 25 एजमेक टैगोर टउन का निवासी है। प्राथी का नाम मधुत्वपूर्ण दस्तावेजों में अखिलेश द्विवेदी है। लेकिन नुटिवश हाई स्कूल हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 1981 के मार्कशीट (707532) अनुक्रमांक में अखिलेश कुमार हो गया है। इसकी जगह मेरा नाम अखिलेश द्विवेदी पढा और लिखा जाए।

